

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2011।

विषय :- रिट याचिका संख्या 1865 (एस/बी)/2001 हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन बनाम राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-558/XXIII/2011/01/रिट/2011 दिनांक 28.07.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या 1865(एम/बी)2001 हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि० बनाम राज्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2010 के क्रम में ₹ 12,72,980/- (₹ बारह लाख बहतर हजार नौ सौ अस्सी मात्र) की धनराशि मै० हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि० को भुगतान किये जाने हेतु डिक्री मद से वित्तीय वर्ष 2011-12 की अनुदान संख्या-07 लेखाशीर्षक, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, 800-अन्य व्यय, 06-मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से सम्बन्धित धनराशि एवं 42-अन्य व्यय मद से आपके निर्वतन पर रखी गई थी, परन्तु वर्तमान में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय दिनांक 23-12-2010 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० संख्या- 5093/2011 दायर की गयी है जो कि अभी मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 28-7-2011 द्वारा आहरित की गयी ₹ 12,72,980/- (₹ बारह लाख बहतर हजार नौ सौ अस्सी मात्र) को वित्त विभाग को समर्पित की जाती है।

3- यदि उक्त याचिका में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को ही भुगतान के आदेश दिये जाते हैं तो वित्त विभाग से पुनः डिक्री मद से धनराशि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जायेगा।

4. अब प्रकरण मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2011-12 की 0039-राज्य उत्पादन शुल्क, 00-800-अन्य प्राप्तियाँ, 05-अन्य व्यय मद में समर्पित की जाती है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 179NP/XXVII(5)/2011-12 दिनांक 16.12.2011 में प्राप्त उनके सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह रावत  
सचिव

संख्या: 1122 / XXIII / 2011 / 01 / रिट / 2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।

3. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनय कुमार, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. नोडल अधिकारी/कोर्ट केसेज/जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।
- ✓ 6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री जी0सी0 ठाकुर, उप प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि0, शिमला।
9. आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ओ0 पी0 तिवारी)

उप सचिव